



हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर



वर्ष:5 अंक:10 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, बुधवार, 14 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की दूरदर्शी सोच से जनता को बड़ी राहत

घर-घर पहुँचा प्रशासन, समाधान और संवेदनशीलता की नई मिसाल

पथ प्रवाह, देहरादून, योगेश शर्मा

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की दूरदर्शी और जनकेंद्रित सोच का प्रत्यक्ष लाभ आज प्रदेश की जनता को मिल रहा है। शासन-प्रशासन की कार्यशैली में आए सकारात्मक बदलाव के चलते अब आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, बल्कि प्रशासन स्वयं घर-घर पहुँचकर जनता की समस्याएं सुन रहा है और उनका त्वरित समाधान कर रहा है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करने का कार्य किया है। इस पहल के



माध्यम से अधिकारी सीधे गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पहुँचकर नागरिकों की

शिकायतों, मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुन रहे हैं। इससे न केवल समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है, बल्कि जनता में सरकार के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है। अभियान के तहत आयोजित जनसमस्या समाधान कैम्पों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही मंच पर उपस्थित रहकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत और नगर निकाय जैसे विभागों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी नागरिक की समस्या अनसुनी न रहे और हर शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया

जाए। यही कारण है कि प्रशासनिक तंत्र पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ मैदान में उतरकर कार्य कर रहा है।

जनता का कहना है कि इस पहल से शासन अब केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह सेवक की भूमिका में दिखाई दे रहा है। प्रशासन का घर-घर पहुँचना सरकार की सकारात्मक सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसंवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया है। यह पहल न केवल जनता को तत्काल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और विकसित उत्तराखंड की नींव भी रख रही है।

उत्तरायणी कौतिक मेला बना सांस्कृतिक संकल्प का मंच

खटीमा को मिली पर्वतीय विकास भवन, मंच निर्माण और कैलेंडर में शामिल होने की सौगात

पथ प्रवाह, खटीमा

कुमाऊँ सांस्कृतिक उत्थान मंच, खटीमा द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित पारंपरिक उत्तरायणी कौतिक मेले का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खटीमा के सांस्कृतिक एवं विकासात्मक भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए मेले को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणा की कि खटीमा में पर्वतीय विकास भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को शीघ्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तरायणी कौतिक मेले को राज्य कैलेंडर में शामिल कर आर्थिक सहायता दिए जाने तथा समिति के अनुरोध पर स्थायी मंच निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। सूर्य के उत्तरायण होने का यह पर्व नई ऊर्जा, नई शुरुआत और आशा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन दर्शन का प्रतीक है और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं।

उन्होंने कहा कि जब बच्चे पारंपरिक वाद्ययंत्रों पर नृत्य करते हैं, युवा लोकगीतों को स्वर देते हैं और माताएं-बहनें पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव में सहभागी बनती हैं, तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित हाथों में है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के साथ-साथ सनातन संस्कृति के



गौरव को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित कर रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को आत्मसात कर उत्तराखंड सरकार देवभूमि को विकास का आदर्श मॉडल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा कि खटीमा उनके लिए केवल विधानसभा नहीं, बल्कि उनका घर है, यहीं से जनसेवा की यात्रा प्रारंभ हुई और यहां का हर व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल, राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक खेल स्टेडियम, गदरपुर-खटीमा बाईपास, नौसर पुल सहित सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है। खटीमा-टनकपुर के बीच भव्य सैन्य स्मारक के निर्माण की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही राजकीय

महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं, तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवभूमि की संस्कृति, डेमोग्राफी और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, 250 से अधिक अवैध मदरसे सील, 500 से अधिक अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गईं तथा ऑपरेशन कालनेमि के तहत पाखंडियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति के चलते लगभग 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और साढ़े चार वर्षों में 200 से



अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए। राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य गठन के मुकाबले 26 गुना बढ़ चुकी है, बजट एक लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 42 हजार से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाकर 2027 का लक्ष्य 2025 में ही प्राप्त कर लिया गया है। डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की धनराशि सीधे खातों में भेजी जा रही है। नंदा गौरा योजना के तहत 40 हजार से अधिक बेटीयों को 172 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की असली वाहक महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में विकास भी होगा, संस्कृति भी बचेगी और राष्ट्रविरोधी मानसिकता को किसी भी कीमत पर स्थान नहीं मिलेगा। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। कार्यक्रम में मेयर दीपक बाली, विकास शर्मा,

नगर पालिका अध्यक्ष रामेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ. प्रेम सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, बीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, सीएमओ डॉ. के.के. अग्रवाल, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी, कुमाऊँ सांस्कृतिक उत्थान समिति अध्यक्ष ठाकुर सिंह खाती, सचिव भुवन चंद्र भट्ट, कोषाध्यक्ष बी.एस. मेहता, मेला प्रभारी के.डी. भट्ट, जे.एस. बसेड़ा, नवीन कापड़ी, किशन सिंह किन्ना, राजेंद्र सिंह मितडी, गोपाल दत्त पाठक, सावित्री चंद, शांति पांडेय, गीता कांडपाल, जानकी गोस्वामी, संदीप कांडपाल, कमला मेलकानी, कुंदन सिंह बोरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में मेलाधीन उपस्थित रहे।

ऋषिकेश की निवर्तमान महापौर अनीता ममगई ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से की शिष्टाचार भेंट

पथ प्रवाह, नई दिल्ली

ऋषिकेश की निवर्तमान महापौर अनीता ममगई ने नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने धर्मनगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम से लाया गया पवित्र गंगाजल राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट कर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक प्रस्तुत किया।

भेंट के दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक महत्व और संगठनात्मक विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। अनीता ममगई ने कहा कि ऋषिकेश केवल एक धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। त्रिवेणी संगम का गंगाजल उसी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस आत्मीय भेंट के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान और संगठनात्मक योगदान की सराहना की। यह मुलाकात सौहार्द, संस्कृति और संगठनात्मक समन्वय का सशक्त संदेश देने वाली रही।



प्रदीप चौधरी, विकास चौधरी, पार्षद सुनील कुमार, विवेक भूषण विक्की, अरशद ख्वाजा, अकरम अंसारी, पूर्व पार्षद कैलाश भट्ट, नितिन तेश्वर, अंजू द्विवेदी, रचना शर्मा, अंजु मिश्रा, लता जोशी, मिलता पांडे, नीतू बिष्ट, दीपाली त्यागी, संजय सैनी, वसीम सलमान, रणवीर शर्मा, जगत सिंह रावत, वीरेंद्र श्रमिक, जितेंद्र विद्याकुल, बृजमोहन बड़धवाल, सत्यपाल शास्त्री, शुभम अग्रवाल, अशोक धोंगान, राजेश पाराशर, नकुल माहेश्वरी, दिनेश पुंडीर, दिनेश दुबे, शाहनवाज, सुभान कुरेशी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।



साल के पहले स्नान पर्व पर सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयार पुलिस: प्रशासन

सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण मेला क्षेत्र 8 जोन और 22 सेक्टरों में बांटा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

साल के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 8 जोन और 22 सेक्टरों में बांटा गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार प्रमोद सिंह डोबाल द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस व प्रशासन के तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में लोहड़ी व मकर संक्रांति स्नान पर्व में लगे फोर्स को ऋषिकुल ऑटोटेरियम में ब्रीफ किया गया।

साल के पहले स्नान का विशेष महत्व होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना के दृष्टिगत एसएसपी हरिद्वार द्वारा फोर्स को पहले से ही मानसिक व शारीरिक तौर पर तैयार रखते हुए सतर्कता से ड्यूटी करने एवं यातायात व्यवस्था के सुव्यवस्थित प्रबंधन को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्दी का समय चल रहा है सभी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अपना ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों को गुप्त रूप से पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी नजर रखते हुए लाभप्रद सूचना से उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये गए। कहा कि प्रत्येक जोनल अधिकारी अन्य अधिकारीगण के साथ मिलकर क्षेत्र के संप्रांत व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। सभी रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं, उन्हें अनुशासन में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करना है। प्रभारी बी.डी.एस. को ब्रीफिंग के बाद संपूर्ण मेला क्षेत्र में सर्वत्र अभियान चलाने एवं 24 घंटे एंटी सबोटाज करते हुए पूरे मेला क्षेत्र



में सतर्क दृष्टि रख समय-समय पर उसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट उच्चाधिकारियों व मेला कंट्रोल को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

ब्रीफिंग के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

विगत स्नानों में देखा गया कि लोहड़ी/मकर संक्रांति स्नान पर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, इसके लिए पहले से ही छोटी बड़ी सभी तैयारी करके रहना है। प्रत्येक जोनल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भीड़ बढ़ने की दशा में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर जनसंख्यिक दबाव को नियंत्रित करेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर नियुक्त पुलिसकर्मी का अपना विशेष महत्व है। थोड़ी सी भी लापरवाही से कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का दृढ़ता एवं संयम के साथ निर्वहन करेंगे।

मंदिरों में न लगे भीड़, कतार में कराएं दर्शन

मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में ड्यूटी



प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि श्रद्धालुगण कतार में ही आगे बढ़ें, भीड़ का दबाव बढ़ने पर तत्काल कंट्रोल रूम को जानकारी देने के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। महिला घाट पर नियुक्त महिला कर्मी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। इस स्थान पर अधिक भीड़ रहती है। प्रत्येक महिला एवं उसके परिजन उसी के आसपास रहते हैं किसी को स्नान के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जाए। महिला घाट से श्रद्धालुओं को लगातार बाहर निकलते हुए उनके गंतव्य को भेजा जाए।

जलपुलिस घाटों पर रखें सतर्क नजर

स्नान के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं के डूबने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जल पुलिस को निर्देश दिये गए कि घाटों पर नियुक्त जल पुलिस की टीमें लगातार मौजूद व सतर्क रहें जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्नान पर्व के पूर्व/दौरान हर की पैड़ी क्षेत्र से भिखारियों को हटाया जाए जिससे



श्रद्धालुगण आसानी से आवागमन कर सकें। स्नान पर्व के दौरान अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए बम निरोधक दस्ते/श्वान दल की टीमें नियुक्त की गई हैं। ये टीमें निरंतर गतिमान रहेंगी। घाटों के संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस अड्डा व अपर रोड मेला क्षेत्र में चेकिंग करते रहेंगे। क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए घुड़सवार पुलिस भी निरंतर गतिमान रहेंगी।

यातायात प्लान का कराएं पालन

पुलिस कर्मियों से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात प्लान तैयार है उसका पूर्ण रूप से पालन करवाया जाए। भीड़ की स्थिति के दृष्टिगत मेला क्षेत्र हेतु यातायात योजना तैयार की गई है। समस्त जोनल/सेक्टर अधिकारी उक्त यातायात योजना का भली भांति अवलोकन कर लें। जोनल अधिकारी, बाईपास जोन, हाईवे पर नियुक्त समस्त सेक्टर प्रभारियों को समय-समय पर ब्रीफ करते हुए

यह सुनिश्चित कर ले कि हाईवे पर किसी भी दिशा में जाम न लगे तथा यातायात सुचारू रूप से चल सके। पर्व समाप्ति तक जनपद में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी अपने पॉइंट से बड़े वाहनों को नहीं छोड़ेंगे।

मेला ड्यूटी में तैनात फोर्स

08 पुलिस उपाधीक्षक, 12 निरीक्षक/थानाध्यक्ष, 87 उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक/महिला उपनिरीक्षक, 131 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 382 हेड कांस्टेबल प्रशिक्षु, 45 महिला आरक्षी, 03 यातायात निरीक्षक, 18 यातायात उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक, 42 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 05 कंपनी+ 01 प्लाटून पीएसी, 02 टीम बम निरोधक दस्ता, 01 टीम एटीएस, 16 कर्मी जल पुलिस/गोताखोर, 16 कर्मी अभिसूचना इकाई, 07 यातायात उप निरीक्षक, 37 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 02 फायर टेंडर मय उपकरण

ज्वालापुर पुलिस का जानलेवा चाइनीज मांझे पर प्रहार, चेकिंग में 10 हजार का चालान



पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से ज्वालापुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में क्षेत्रभर में सघन चेकिंग एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ज्वालापुर क्षेत्र में पतंग और मांझा विक्रय करने वाली दुकानों की गहन जांच की गई। पुलिस टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आमजन, विशेषकर बच्चों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में किसी भी स्तर पर इसकी बिक्री या भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेकिंग के दौरान पीठ बाजार, ज्वालापुर निवासी हिमांशु जायसवाल उर्फ भोला पुत्र अनिल जायसवाल के कब्जे से अल्प मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 10,000 का चालान काटते हुए कड़ी कार्रवाई की। साथ ही सभी दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा प्रतिबंधित मांझे की बिक्री की गई तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज्वालापुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार ने जनता से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से दूर रहें तथा कहीं भी अवैध बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारी: उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार (एसएसआई ज्वालापुर), कांस्टेबल अमित गौड़, कांस्टेबल संजय रावत, कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल राजेश बिष्ट (चेतक कर्मी)।

नगर निगम ने प्रेमनगर पुल से हटाया अतिक्रमण, स्वच्छता अभियान में हटाए कूड़े के ढेर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, एवं सुंदर बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले 65 दिन से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जहां शहर से लेकर गांव की गलियों तक सफाई कार्य किये जा रहे हैं वहीं अतिक्रमण हटाकर जनपद को सुंदर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भी अभियान जारी रहा।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में निरंतर चल रहे सफाई अभियान के तहत नगर निगम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण भी हटाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नव वर्ष के अवसर पर महा सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सभी जनपदवासियों ओर धार्मिक संस्थाओं, व्यापार मंडलों, जनप्रतिनिधियों, गैर स्वयंसेवी संगठनों इस अभियान में पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई है। मंगलवार



को बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने बताया बीएचईएल द्वारा निकट खोखा मार्केट एवं ओल्ड पीएनबी बिल्डिंग सेक्टर-5 बी क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई का कार्य किया गया। उपनगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा प्रेमनगर पुल सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाया गया साथ ही क्षेत्र की सफाई अभियान चलाया गया। खण्ड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया कि ग्राम



पंचायत सिकन्दरपुर, प्रह्लादपुर व गोरधनपुर क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई का कार्य किया गया। खण्ड विकास अधिकारी रूडकी ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत अकबरपुर झोझा एवं लाठरदेवा श्रेष्ठ क्षेत्रांतर्गत सफाई का कार्य किया गया। खण्ड विकास अधिकारी नारसन ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत गोपालपुर, बुक्कपुर एवं राजपुर मुस्तफाबाद क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई का कार्य किया गया।

रानीपुर मोड़ पर कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

रानीपुर मोड़ पर देर शाम अचानक एक खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

बताया जा रहा है कि जिस जगह कार खड़ी हुई थी उस स्थान पर कुछ देर पहले लोहड़ी जलायी गई थी। आशंका जतायी जा रही है कि गरम राख से निकली चिंगारी की वजह से कार में आग लगी। हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं है। जिस समय कार में आग लगी उस वक्त मौके पर मौजूद



ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर हितेश कुमार और उनकी टीम ने त्वरित रिसॉन्स देते हुए आसपास की दुकानों से अग्निशामक यंत्र मंगवाकर आग को फैलने से रोका। उसके

बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह बुझाया दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से कार को काफी नुकसान हुआ है।

संपादकीय

नदी संरक्षण: विकास और संवेदनशीलता का संतुलन

भारत की नदियाँ केवल जलधाराएँ नहीं हैं, बल्कि वे देश की संस्कृति, आस्था, जैवविविधता और आजीविका की आधारशिला रही हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ सदियों से भारतीय सभ्यता को जीवन देती आई हैं। किंतु आधुनिक समय में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण और मानवीय हस्तक्षेप ने इन नदियों के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे में नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताना केवल एक वक्तव्य नहीं, बल्कि समय की अनिवार्य मांग है।

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केन्द्र का लोकार्पण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। यह केन्द्र न केवल नदियों और मीठे पानी के पारिस्थितिकीय तंत्रों से जुड़े वैज्ञानिक ज्ञान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि नीति निर्माण, संरक्षण रणनीतियों और व्यवहारिक समाधानों के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा।

नदियों की स्वच्छता केवल जल की गुणवत्ता तक सीमित विषय नहीं है। यह सीधे तौर पर जलीय जैवविविधता, जैसे डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए और दुर्लभ पक्षियों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन का शुभारंभ इस बात का प्रमाण है कि अब संरक्षण केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आपातकालीन प्रतिक्रिया और जमीनी कार्रवाई की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

गंगा संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों और गंगा प्रहरियों की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संरक्षण तभी स्थायी हो सकता है जब वह आजीविका से जुड़ा हो। सामुदायिक सहभागिता और आजीविका आधारित संरक्षण मॉडल यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं।

राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केन्द्र जैसे संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान को नीति और समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। घड़ियाल, कछुआ और इंडियन स्किमर जैसे संकटग्रस्त जीवों पर केंद्रित परियोजनाएँ यह दर्शाती हैं कि भारत अब प्रजाति-विशेष संरक्षण से आगे बढ़कर संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की दिशा में सोच रहा है।

आज जब जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जैवविविधता क्षरण वैश्विक चुनौती बन चुके हैं, भारत का यह प्रयास न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश है। नदियों का संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक दायित्व भी है।

यह समझना आवश्यक है कि नदी बचेगी तो जीवन बचेगा। राष्ट्रीय नदी अनुसंधान केन्द्र जैसे प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होंगे, जब नीति, विज्ञान और समाज एक साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ें। यही संतुलन भारत को विकास के साथ-साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशील राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है।

नार्को-टेरर-मिशन ड्रग फ्री इंडिया @2029:नशे के खिलाफ़ भारत की निर्णायक लड़ाई

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

ड्रग फ्री इंडिया @2029 का लक्ष्य केवल एक सरकारी नारा नहीं बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों सामाजिक स्थिरता और आर्थिक क्षमता को सुरक्षित रखने की एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है

वैश्विक स्तरपर भारत ने पिछले एक दशक में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जिस प्रकार का निर्णायक बदलाव देखा है, वह न केवल राष्ट्रीय राजनीति बल्कि अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक समुदाय के लिए भी अध्ययन का विषय बन गया है। नक्सलवाद, जिसे लंबे समय तक भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना गया, उसके विरुद्ध 31 मार्च 2026 तक समाप्ति का लक्ष्य तय कर जिस तरह ठोस, बहु-स्तरीय और निरंतर अभियान चलाया गया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय और सुरक्षा बलों की पेशेवर क्षमता के साथ असंभव माने जाने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ भारत सरकार अब दूसरी, कहीं अधिक जटिल और वैश्विक जड़ों वाली चुनौती,ड्रग्स और नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के चरण में प्रवेश कर चुकी है। ड्रग फ्री इंडिया @2029 का लक्ष्य केवल एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों सामाजिक स्थिरता और आर्थिक क्षमता को सुरक्षित रखने की एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नीति से आगे बढ़कर समयबद्ध, परिणाम-आधारित और मिशन मोड में काम करने में सक्षम है।दशकों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समानांतर सत्ता,हिंसा,विकास अवरोध और मानवाधिकार संकट की स्थिति अब भी रही। परंतु पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण,

खुफिया तंत्र की मजबूती, स्थानीय विकास योजनाओं और राजनीतिक संकल्प ने इस चुनौती की कमर तोड़ दी। यही मॉडल अब ड्रग्स के खिलाफ़ अपनाने की तैयारी है लेकिन अंतर यह है कि नशा केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बहुआयामी संकट है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसे नार्को- टेरर की संज्ञा देना इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है, क्योंकि ड्रग्स का पैसा आतंकवाद संगठित अपराध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित करता है।ड्रग फ्री इंडिया @2029 का लक्ष्य इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने नशा मुक्त समाज की दिशा में एक स्पष्ट समय-सीमा, संस्थागत रोडमैप और बहु-विभागीय उत्तरदायित्व तय किया है।

साथियों बात अगर हम नई दिल्ली में आयोजित एनकोर्ड की 9वीं उच्च स्तरीय बैठक को समझने की करें तो,यह इसी रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों,राज्य सरकारों और ड्रगकानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि यह लड़ाई किसी एक एजेंसी या राज्य की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी है।बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल आंकड़ों की समीक्षा नहीं, बल्कि नशा तस्करी नेटवर्क और गैंग को जड़ से तोड़ने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करना था।ड्रग्स के खिलाफ इस नए अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका 360- डिग्री दृष्टिकोण है।पारंपरिक रूप से ड्रग्स को सीमा सुरक्षा या पुलिसिंग की समस्या के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब इसे एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समझा जा रहा है, जहां उत्पादन,तस्करी,फाइनेंसिंग तकनीक उपभोक्ता मांग और सामाजिक कमजोरियां आपस में गहराई से जुड़ी हैं।

संवाद

तिल-गुड़ की मिठास में बसा सूर्य पर्व है ‘मकर संक्रांति’

योगेश कुमार गोयल

मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का ऐसा प्राचीन पर्व है, जिसकी जड़ें केवल धार्मिक आस्था में ही नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि, खगोल विज्ञान और लोकजीवन की गहरी समझ में भी समाई हुई हैं। यह पर्व मूलतः सूर्य उपासना का उत्सव है, जिसे प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ भारत सहित अनेक देशों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि यह पर्व किसी पौराणिक कथा तक सीमित न होकर खगोलीय घटना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ करता है, जिसे अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और जड़ता से चेतना की ओर संक्रमण का प्रतीक माना गया है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है।

मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ऋतु परिवर्तन का सजीव संकेत भी है। इसी दिन से वसंत ऋतु के आगमन की आहट मिलने लगती है। खरीफ की फसलें घरों तक पहुंच चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहाने लगती हैं। सरसों के पीले फूल खेतों में प्रकृति की मुस्कान बिखरते हैं और किसान के श्रम का प्रतिफल उसकी आंखों के सामने साकार होने लगता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को देशभर में फसलों के आगमन और कृषि समृद्धि के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। यह उत्सव किसान के लिए आशा, संतोष और भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य देव अपने सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह परिवर्तन केवल खगोलीय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव से वर्षों पुरानी नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे, इसलिए यह पर्व पारिवारिक समरसता, क्षमा और संबंधों की



पुनर्स्थापना का संदेश भी देता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी दिन तर्पण किया था, जिससे इस तिथि को पितृ तर्पण और पुण्यकर्म से भी जोड़ा गया।

खगोल विज्ञान की दृष्टि से मकर संक्रांति का महत्व अत्यंत वैज्ञानिक है। पृथ्वी की गोलाकार संरचना और उसके अक्ष पर झुके हुए भ्रमण के कारण दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, तब उत्तरी गोलार्द्ध में दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। लोकभाषा में कहा जाता है कि मकर संक्रांति से दिन 'तिल-तिल' बढ़ता है। दिन की अवधि बढ़ने से खेतों में बोए गए बीजों को अधिक प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, जिससे फसलों की वृद्धि बेहतर होती है। यही कारण है कि यह पर्व किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है और कृषि आधारित भारतीय समाज में इसका गहरा स्थान है। 'मकर' शब्द जहां मकर राशि की ओर संकेत करता है, वहीं 'संक्रांति' का शाब्दिक अर्थ है-संक्रमण या प्रवेश। सूर्य जब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उस खगोलीय घटना को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य वर्षभर में कुल बारह राशियों में क्रमशः प्रवेश करता है, परंतु मकर संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि यह उत्तरायण का प्रारंभ बिंदु है।

भारतीय परंपरा में उत्तरायण काल को अत्यंत शुभ माना गया है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए देह त्याग किया था, जिससे इस काल की पुण्यता और अधिक स्थापित होती है।

मकर संक्रांति की एक विशिष्ट विशेषता यह भी है कि यह भारत का ऐसा पर्व है, जो लगभग पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, हालांकि इसके नाम, परंपराएं और स्वरूप क्षेत्र विशेष के अनुसार बदल जाते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व कहीं लोहड़ी, कहीं खिचड़ी, कहीं माघी तो कहीं पतंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्य भारत में इसे सामान्यतः संक्रांति कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में यही पर्व 'पोंगल' के रूप में महापर्व का दर्जा रखता है। कहीं इसे उत्तरायण कहा जाता है तो कहीं पौष संक्रांति। असम में यह भोगाली बिहू या माघ बिहू कहलाता है, तो बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। भारत की सीमाओं से बाहर भी मकर संक्रांति का सांस्कृतिक विस्तार देखने को मिलता है।

नेपाल में यह माघे संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। श्रीलंका में इसे पोंगल या उल्लव तिरूनल कहा जाता है। बांग्लादेश में पौष संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, म्यांमार में थिंगान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान और लाओस में पि मा लाओ के नाम से यह पर्व मनाया जाता है।

वैश्विक उथल-पुथल में भारतीय विवेक और विकास का संतुलन

नीलेश वर्मा

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य गहरी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और हम भारतीय आनंद के साथ अपने तीज-त्यौहार मना रहे हैं, पूरे देश में भव्य रूप में विभिन्न उत्सवों व समारोहों का आयोजन हो रहा है। हमें यह भी याद रखना होगा कि इसके पीछे हमारे पूर्वजों का बलिदान और भावी योजना है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मध्य-पूर्व के अनेक हिस्सों में युद्ध, गृहसंघर्ष, सत्ता संघर्ष और तख्तापलट की घटनाएँ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रही हैं। सीमाई विवाद सशस्त्र टकराव में बदल रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएँ दबाव में हैं और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर दिख रहा है। परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट, बढ़ती महंगाई और आपूर्ति-श्रृंखला में बाधाओं ने विशेष रूप से विकासशील देशों के सामने अस्तित्व और स्थिरता की दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है।

ऐसे संकटों से भरे वातावरण में भारत का दृष्टिकोण संतुलित, परिपक्व और दूरदर्शी दिखाई देता है। जहाँ कई देश युद्ध और टकराव को ही समाधान मान रहे हैं, वहीं भारत ने कूटनीति, संवाद और संयम को प्राथमिकता दी है। भारत ने यह करके दिखाया है कि स्थायी समाधान शक्ति-प्रदर्शन से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णयों से निकलता है। पड़ोसी पाकिस्तान के संदर्भ में भी भारत का यही दृष्टिकोण रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों में भारत ने सैन्य दृढ़ता के साथ-साथ रणनीतिक संयम का परिचय दिया। उकसावे के बावजूद स्थिति को व्यापक युद्ध में बदलने से रोकना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों के साथ शांतिपूर्ण पक्ष रखना और क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देना भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

आज पूरा विश्व देख रहा है बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो

रहा है, अमेरिका-रूस और वेनेजुएला विवाद, ईरान में आंतरिक विरोध, इजरायल-लेबनान संघर्ष, मध्य-पूर्व में तनाव, सीरिया की सैन्य कार्रवाइयाँ, यूक्रेन, गाजा, सूडान और म्यांमार के युद्ध, अफ्रीका में तख्तापलट, चीन-ताइवान तनाव, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा, अफगानिस्तान की अस्थिरता और नेपाल की राजनीतिक कमजोरी यह सब दर्शाता है कि वैश्विक व्यवस्था गहरे संकट में है। ऐसे समय में भारत का संयमित व्यवहार और विकास-केंद्रित सोच यह संदेश देती है कि स्थायी शक्ति संवाद, सामाजिक सद्भाव और समावेशी प्रगति से ही बनती है।

इन सबके बावजूद भारत के भीतर विकास की गति निरंतर बनी रही। सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढाँचों का विस्तार होने के साथ ही डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीकी समावेशन, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलना भारत की विकास-केंद्रित नीति को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति के नागरिक तक विकास पहुँचाने का प्रयास जारी है। नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में उठाए गए कदमों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को मजबूत आधार दिया है। भारत ने विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा है। एक ओर सैन्य तैयारी और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। यही संतुलन भारत को उन देशों से अलग करता है, जहाँ सत्ता संघर्ष और अस्थिरता ने विकास को वर्षों पीछे धकेल दिया।

देश के भीतर सुधारों की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से आगे बढ़ी है। महिला आरक्षण, जीएसटी के माध्यम से कर-व्यवस्था का एकीकरण, तीन तलाक पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 370 का निरसन, नागरिकता

संशोधन अधिनियम, नई शिक्षा नीति, श्रम संहिताओं का सरलीकरण, दिवालियापन संहिता, डिजिटल डेटा संरक्षण कानून, औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों के स्थान पर नई न्याय संहिताएँ, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त प्रावधान तथा चुनावी-प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एसआईआर जैसे कदम यह दर्शाते हैं कि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर लागू किए जा रहे हैं। विकास के ये प्रयास जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिनमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत स्टेशन योजना, अयोध्या, काशी और सोमनाथ का सांस्कृतिक पुनर्विकास, मुंबई की कोस्टल रोड और अटल सेतु, सौर-पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का विस्तार, हर-घर जल योजना, गगनयान और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में निवेश तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क-सुरंग-पुल निर्माण ने यह साबित किया है कि भारत की विकास योजनाएँ ठोस कार्यों में बदल रही हैं।

वर्ष 2025 में सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने विवेकपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़-तेलंगाना के सीमावर्ती जंगलों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत नक्सल-माओवादी नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई की गई। बीजापुर (छत्तीसगढ़) में नक्सली हिंसा के बाद क्षेत्र-नियंत्रण और तलाशी अभियान चलाए गए। नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सतत गश्त और त्वरित तैनाती से स्थिरता बनाए रखी गई। साथ ही अजेय वॉरियर-25 (राजस्थान), हरिमाऊ शक्ति-2025 (मलेशिया), ऑस्ट्राहिंद-2025 (ऑस्ट्रेलिया) और ब्राइट स्टार-2025 (मिस्र) जैसे अभ्यासों से अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग को मजबूती मिली। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल-2025 और रक्षा आधुनिकीकरण ने भारत की तैयारी को और सुदृढ़ किया।



मुजफ्फरनगर का उभरता गैंग देहरादून में धराशायी, घर का भेदी लूट का मास्टरमाइंड

एसएसपी दून के नेतृत्व में दून पुलिस की बड़ी कामयाबी, पटेलनगर लूट कांड का खुलासा

पथ प्रवाह, देहरादून।

कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूट की घटना का दून पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए मुजफ्फरनगर के उभरते गैंग के पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस वारदात का मास्टरमाइंड वादी की फुफेरी बहन का पति निकला। एसएसपी देहरादून अजय सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों ने सतर्कता, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के सहारे इस संगठित अपराध का पर्दाफाश किया।

09 जनवरी 2026 को वादी शराफत पुत्र दिलशाद अली निवासी मकान संख्या-03, वन विहार मेहूवाला, देहरादून ने कोतवाली पटेलनगर में तहरीर दी कि 04 अज्ञात अभियुक्तों ने रात में घर में घुसकर परिजनों से मारपीट कर लगभग एक लाख रुपये नकद व कुछ ज्वैलरी लूट ली। तहरीर के आधार पर



मु0अ0सं0-15/2026

धारा

331(4)/309(6)/3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सदिग्धों की गतिविधियों का विश्लेषण किया और मुखबिरों

को सक्रिय किया। लगातार प्रयासों के बाद 13 जनवरी 2026 को तेलपुर चौक के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों-बुशरान राणा, आसिफ उर्फ बबलू, इफान, राजकुमार उर्फ अनिल और वासिफ-को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 91,950 रुपये

नकद, 02 अवैध तमंचे (.315 बोर), 04 जिंदा कारतूस, 02 अवैध चाकू और 01 आलानकब बरामद हुआ।

पूछताछ में मास्टरमाइंड बुशरान राणा ने कबूला कि उसे वादी द्वारा सहारनपुर में जमीन के करोड़ों के सौदे और 1.80 करोड़ रुपये बयाने की संभावित राशि की जानकारी थी। सौदा कैसिल होने से अभियुक्तों को अपेक्षित रकम नहीं मिली और वे केवल नकदी व ज्वैलरी लेकर फरार हो गए। लूटी गई ज्वैलरी की बरामदगी हेतु अभियुक्तों का पीसीआर लिया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त

बुशरान राणा पुत्र स्व. याकूब, निवासी शिवपुरी नई बस्ती, थाना खतौली, मुजफ्फरनगर (31 वर्ष), आसिफ उर्फ बबलू पुत्र स्व. बाबू, निवासी शिव मंदिर रोड, खतौली (35 वर्ष), इरफान पुत्र स्व. छौनी, निवासी किजियान मोहल्ला, मुजफ्फरनगर

(45 वर्ष), राजकुमार उर्फ अनिल पुत्र स्व. बलदेव, निवासी ग्राम उमरपुर, थाना बुढाना (55 वर्ष), वासिफ पुत्र स्व. जहीर, निवासी कजियान मोहल्ला, रहमतनगर, बधरा (36 वर्ष)

पुलिस टीम

निरीक्षक चन्द्रभान सिंह अधिकारी (प्रभारी निरीक्षक), उ0नि0 आशीष कुमार, उ0नि0 मुकेश थलेडी, हे0कानि0 मनोज कुमार, हे0कानि0 सुनीत कुमार, कानि0 बृजेश कुमार, कानि0 अरशद अली, कानि0 आबिद अली, कानि0 आजाद, हे0कानि0 हरेन्द्र पवार, कानि0 विनोद राणा, कानि0 गौरव कुमार, कानि0 विक्रान्त कुमार, उ0नि0 संदीप पवार (डाकपत्थर), कां0 बृजपाल, कां0 रविन्द्र चौहान, कां0 राजकुमार चौधरी, कां0 नितिन, कां0 नवीन कोहली। एसओजी टीम उ0नि0 शैकी कुमार, कानि0 ललित कुमार, कानि0 ललित कुमार।

एक नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने परिजनों को दिलाया न्याय का भरोसा

पथ प्रवाह, देहरादून/काशीपुर। काशीपुर क्षेत्र के किसान स्वर्गीय सुखवंत सिंह की मृत्यु के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण की जांच में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिवंगत किसान के भाई परविंदर सिंह से दूरभाष पर बातें कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिवार को ढाढस बंधाया। इस दौरान दिवंगत सुखवंत सिंह के पिता एवं अन्य परिजन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल उच्चाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए कुमाऊं आयुक्त को मजिस्टीरियल जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो सरकार त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि हर हाल में उन्हें ईसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे शीघ्र ही स्वयं पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार संवेदनशीलता, मानवता और न्याय के सिद्धांतों के साथ इस पूरे मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचायेगी।

भारत ने संभाली ब्रिक्स 2026 की कमान, विदेश मंत्री ने लॉन्च किये आधिकारिक लोगो, वेबसाइट

नयी दिल्ली। भारत ने मंगलवार को 10 देशों के समूह 'ब्रिक्स' की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभालते हुए वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इस वर्ष के अंत में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कमल के आकार वाले लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता और इस लोगो के माध्यम से 'मानवता प्रथम और जन-केंद्रित दृष्टिकोण' को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास ब्रिक्स देशों की क्षमता को वैश्विक कल्याण के लिए एकजुट करना होगा। डॉ. जयशंकर ने कहा, 'जब भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है, तो यह इस समूह की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।' उन्होंने कहा कि 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर लेगा। इन वर्षों में यह समूह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक 'महत्वपूर्ण मंच' के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा, 'बीते सालों में ब्रिक्स ने बदलती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने एजेंडे और सदस्यता का विस्तार किया है। साथ ही आम जनता को केंद्र में रखने वाला विकास इस समूह की प्राथमिकता रहा है, जिससे बातचीत और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा मिला है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक वातावरण जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक विषमताओं, जलवायु जोखिमों और तकनीकी परिवर्तनों से घिरा है। ऐसे में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संवाद, सहयोग और व्यावहारिक समाधानों को प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने लोगो की विशेषता बताते हुए कहा कि इसमें परंपरा और आधुनिकता का समावेश है। इसकी पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के झंडों के रंग शामिल हैं, जो विविधता में एकता और साझा उद्देश्य की भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगो इस बात का प्रतीक है कि जहां ब्रिक्स की ताकत उसके सदस्यों के साझे योगदान से आती है, वहीं उनकी निजी पहचान का भी सम्मान किया जाता है। भारत ने ब्रिक्स की परिवर्ती (बारी-बारी से मिलने वाली) अध्यक्षता ब्राजील से ग्रहण की है। भारत इस दौरान वैश्विक दक्षिणी देशों (विकासशील देशों) के सहयोग, समावेशी शासन और नवाचार पर जोर देगा। जी-20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के बाद, भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता को भी व्यापक स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसके तहत देश के 60 शहरों में साल भर में 100 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ब्रिक्स को 'ब्रिलियंट रेजिलिएंस एंड इन्वेंशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' के रूप में परिभाषित करने का सुझाव दिया है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं में स्थानीय मुद्दों में व्यापार को बढ़ावा देना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, एआई नीत प्रशासन, अंतरिक्ष अन्वेषण और आतंकवाद विरोधी वैश्विक रणनीति बनाना शामिल रहने की संभावना है।

पथ प्रवाह, देहरादून।

जनपद में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निर्धारित मानकों से अधिक शस्त्र रखने तथा एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट न कराने वाले कुल 827 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में की गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा आयुध (संशोधन) नियम-2019 के अंतर्गत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या तीन से घटाकर दो निर्धारित की गई है। इसके अनुपालन में उत्तराखंड शासन ने सभी जिलों को निर्देशित किया था कि निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 26 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, जिनके नाम पर दो से अधिक शस्त्र दर्ज थे। नोटिस के बावजूद 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा न तो कोई प्रतिउत्तर दिया



गया और न ही अतिरिक्त शस्त्र हटाए गए। जांच में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर इन 54 लाइसेंस धारकों के नाम पर दो से अधिक शस्त्र अंकित पाए गए।

जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत, शूटिंग खेल प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस धारकों को छोड़ते हुए, इन 54 शस्त्र धारकों के नाम पर दर्ज सभी अतिरिक्त शस्त्र एवं संबंधित लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही इन शस्त्रों और लाइसेंसों को एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल से भी विलोपित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन ने बिना यूआईएन जनरेट कराए गए शस्त्र लाइसेंसों पर भी सख्त कार्रवाई की है। उत्तराखंड शासन के गृह अनुभाग-05 द्वारा जारी शासनादेशों (03

मई 2017, 09 मार्च 2023 एवं 03 सितम्बर 2025) के अनुसार 30 जून 2020 के बाद जिन शस्त्र लाइसेंसों में यूआईएन जनरेट नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त किए जाने के निर्देश हैं।

इन निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से शस्त्र धारकों को अवगत कराया गया था और बिना यूआईएन वाले लाइसेंस धारकों से नवीन ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया गया। बावजूद इसके जनपद देहरादून में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर 773 शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन के पाए गए।

जिला प्रशासन ने शासनादेशों के अनुरूप इन सभी 773 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करते हुए पोर्टल से विलोपित कर दिया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की बड़ी भर्ती, 365 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे नियुक्त

पथ प्रवाह, देहरादून।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से चली आ रही फैकल्टी की कमी अब शीघ्र दूर होने वाली है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 365 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी कर ली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संकायवार रोस्टर सहित भर्ती प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शत-प्रतिशत स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति करना है। इसी क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शासन स्तर से अनुमोदन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा जाएगा। डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी



दी कि श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ स्थित सात राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कुल 27 संकायों के अंतर्गत यह भर्ती की जाएगी। विभाग द्वारा तैयार किए गए रोस्टर में बैकलॉग के रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावित 365 पदों में अनुसूचित जाति के 115, अनुसूचित जनजाति के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 67, आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग के 37 तथा अनारक्षित श्रेणी के 136 पद शामिल हैं।

डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 567 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष केवल 202 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर ही कार्यरत हैं, जबकि 365 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर शीघ्र भर्ती होने से कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों को अनुभवी एवं योग्य फैकल्टी का लाभ मिलेगा।

विभागों की बात करें तो एनार्टोमी, बायोकैमिस्ट्री, ब्लड बैंक और फोरेंसिक मेडिसिन में कुल 8 पदों पर भर्ती होगी। फिजियोलॉजी में 13, पैथोलॉजी में 18, माइक्रोबायोलॉजी व डमेंटोलॉजी में 6-6, फार्माकोलॉजी में 12, कम्युनिटी मेडिसिन में 21 तथा जनरल मेडिसिन में सर्वाधिक 49 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जनरल सर्जरी में 44, ऑब्स एंड गायनी में 37, पीडियाट्रिक्स में 19, ऑर्थोपेडिक्स और रेडियोडायग्नोसिस में 17-17 पद शामिल हैं।



कार्यकर्ताओं का स्नेह और संगठन की स्मृतियाँ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी : त्रिवेन्द्र सिंह रावत

पथ प्रवाह, देहरादून

‘मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व के अवसर पर पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के बीच रहना आत्मिक आनंद से भर देता है। संगठन की जड़ें इन्हीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से मजबूत होती हैं,’ यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कही।

उन्होंने मकर संक्रांति के पूर्व दिवस पर रायपुर क्षेत्र के सोडा सरोली में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों के साथ आयोजित



सहभोज कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने पुराने साथियों से आत्मीय भेंट कर उनका हालचाल जाना तथा संगठन से जुड़ी अनेक स्मृतियाँ साझा कीं।

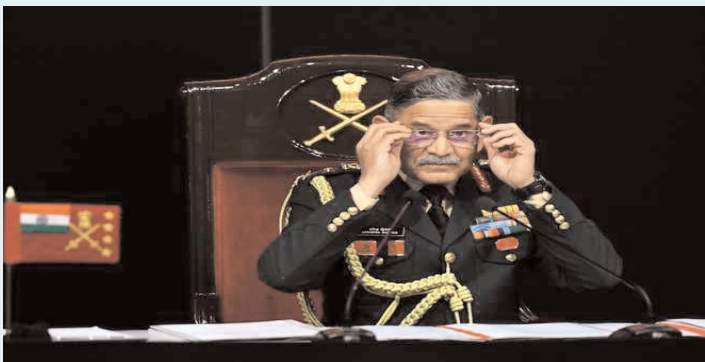
त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे आयोजन संगठन और समाज के बीच आपसी विश्वास व संवाद को और मजबूत करते हैं। उन्होंने इस आत्मीय और विशेष आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी।

एक नजर

मोबाइल सौंपने से पहले बिगड़ी उर्मिला सनावर की तबियत

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वायरल आडियो मामले में एसआईटी के सामने पेश होने से पहले अभिनेत्री उर्मिला सनावर की तबियत बिगड़ने की जानकारी सामने आयी है। जिसके बाद मंगलवार को उनके मोबाइल फोन सौंपने की प्रक्रिया टल गई है। सुबह जानकारी सामने आयी कि उसकी तबियत खराब हो गई है, और वह अपना अस्पताल में इलाज करा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका इलाज कराते हुए फोटो भी सामने आया है। मंगलवार को उर्मिला सनावर को अपना मोबाइल फोन सौंपने के लिए हरिद्वार एसआईटी के समक्ष पेश होना था, जहां उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका मोबाइल फोन जांच के लिए कब्जे में लिया जाता। लेकिन अचानक उनकी तबियत बिगड़ने से वह हरिद्वार नहीं पहुंची जिस कारण उनके मोबाइल सौंपने की प्रक्रिया टल गई। बता दें पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच कथित बातचीत का आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें अंकिता हत्याकांड को लेकर कथित वीडियो का नाम भी लिया गया। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमे भी दर्ज हुए। मुकदमों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी द्वारा पूर्व में की गई पूछताछ के दौरान दोनों ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया था। एसआईटी मोबाइल और संबंधित आडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, ताकि आडियो की प्रामाणिकता, समय-सीमा और अन्य तकनीकी पहलुओं की पुष्टि हो सके। एसआईटी का कहना है कि उर्मिला की सेहत में सुधार के बाद मोबाइल जब्ती और आगे की जांच कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन तीनों सेनाओं की गतिविधियों की भनक लगते ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिये : जनरल द्विवेदी



नयी दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता और सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों और दावों के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि इस अभियान के दौरान दस मई की सुबह तीनों सेनाओं को शीर्ष स्तर पर दिये गये कुछ निर्देशों के बाद पाकिस्तान की समझ में आ गया कि अब युद्ध को रोकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सेना उस समय पूर्ण जमीनी ऑपरेशन के लिए भी तैयार थी और पाकिस्तान को इसकी भनक भी लग गयी थी। सेना प्रमुख ने मंगलवार को 78 वें सेना दिवस से पहले यहां वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सवाल के जवाब में कहा कि इस ऑपरेशन में दो निर्णायक मोड़ थे।

पहला निर्णायक मोड़ सात मई की रात का 22 मिनट का हमला था जो सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर किया। इस हमले से पाकिस्तान की निर्णय लेने की व्यवस्था हिल गयी और अफरा-तफरी मचने से उन्हें यह समझने में समय लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरा निर्णायक मोड़ 10 मई की सुबह उस समय आया जब शीर्ष स्तर से तीनों सेनाओं को कुछ निर्देश दिए गए थे कि यदि यह युद्ध और बढ़ता है तो क्या होगा। उन्होंने कहा जिन्हें (पाकिस्तान) यह समझना था, उन्होंने इसे समझ लिया। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें (पाकिस्तान को) उपग्रहों के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी मिल रही थी कि कौन सा युद्धपोत, कौन सा हमला या रणनीतिक मोड़, कौन सा मुख्य इकाई या कौन सा विमान कब और कहाँ जा रहा है। जब उन्होंने इन सभी बिन्दुओं और बातों को आपस में जोड़ा तो उन्हें समझ में आग गया कि अब इस युद्ध को रोकने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सेना ने पारंपरिक हथियारों से भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत के नागरिक इलाकों में फायरिंग के बाद भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान के करीब 100 सैनिक मारे गये। ये सब नियंत्रण रेखा पर मारे गये। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर पाये क्योंकि हमने पारंपरिक युद्ध का विस्तार करते हुए उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तैनाती और तैयारी इस तरह की गई थी कि पारंपरिक युद्ध स्थिति को और फैलाया जा सके और यदि पाकिस्तान कोई भी गलती करता तो हम जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा में सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में की सहभागिता

पथ प्रवाह, खटीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नगला तराई रोड स्थित हर्षु इन्क्लेव में सुमित गुम्बर के आवास पर आयोजित सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि लोहड़ी पर्व आपसी भाईचारे, खुशहाली और नई ऊर्जा का प्रतीक है। यह पर्व समाज में एकता, सौहार्द और सांस्कृतिक समरसता को मजबूत करता है। उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में मेयर दीपक बाली, विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रामेश चंद्र



जोशी, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ प्रेम सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, वीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश

शासनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ उत्तम सिंह नेगी, सीएमओ डॉ के.के. अग्रवाल, उप जिलाधिकारी तुषार सेनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसियेशन ने सरकार के प्रयासों की सराहना की

पथ प्रवाह, देहरादून।

राज्य में फिल्मों की शूटिंग एवं क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसियेशन ने सराहना की है। एसोसियेशन का कहना है कि प्रभावी एवं आकर्षक फिल्म नीति लागू किए जाने से राज्य के स्थानीय एवं क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को बड़ा लाभ मिल रहा है।

मंगलवार को उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसियेशन के प्रतिनिधिमंडल ने रिंग रोड स्थित सूचना भवन में महानिदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय फिल्मों को अनुदान दिए जाने तथा सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं फिल्म विकास परिषद का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में राज्य में फिल्म नीति-2024 लागू की गई है, जिसमें स्थानीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार एवं तकनीशियनों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में शूट की गई फिल्मों को कुल व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, टीवी



सीरियल, डॉक्यूमेंट्री एवं लघु फिल्मों को भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

बंशीधर तिवारी ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव एवं फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के उपक्रम एनएफडीसी (ह्रस्वछट्ट) से पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद की वेबसाइट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी स्थानीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन एवं लाइन प्रोड्यूसर का विस्तृत डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।

उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसियेशन के संरक्षक अनुज जोशी ने परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जुलाई 2025 में फिल्मों को अनुदान देने हेतु गठित समिति की बैठक में स्थानीय फिल्मों को

अनुदान प्रदान किया गया, जिसके लिए क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े सभी निर्माता एवं निर्देशक

राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने राज्य में फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर फिल्म नीति के सकारात्मक परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड में स्थानीय फिल्म निर्माण गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन उपाध्याय, उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसियेशन के उपाध्यक्ष बृजेश भट्ट, महासचिव गंभीर जयाड़ा तथा सदस्य जितेंद्र पंवार, हरीश नेगी, विजय शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।



जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नन्दा देवी मंदिर में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने मंगलवार सुबह नन्दा देवी मंदिर परिसर में चल रहे विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों तथा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने मंदिर परिसर में स्थापित बिजली के खंभों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिर की बाउंड्री, मंदिर प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्यों एवं अन्य निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्थानीय निवासियों की आपत्तियों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नन्दा देवी



मंदिर एक प्राचीन एवं सांस्कृतिक धरोहर है, जिसके संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने निर्देशित किया कि मंदिर के प्राचीन स्वरूप को

संरक्षित रखते हुए ही सभी कार्य किए जाएँ तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर समिति एवं प्रशासन आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि



मंदिर परिसर का विकास और धरोहर संरक्षण संतुलित रूप से सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी संजय कुमार, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी चंद्र सिंह

चौहान, मंदिर समिति से मनोज वर्मा एवं मनोज सनवाल, पार्षद अमित साह, पार्षद अर्जुन बिष्ट सहित अन्य संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जन जन की सरकार के बहुउद्देशीय शिविर में 1022 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीआर चौहान की अध्यक्षता में विकास खंड नारसन के न्याय पंचायत नारसन कलां के जूनियर हाई स्कूल में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से 237 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न विभागों के माध्यम से 56 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। इस शिविर में 2209 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग। आयोजित शिविर में क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 68 समस्याएं दर्ज कराई गईं, जिसमें 29 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। बहुउद्देशीय शिविर को संबोधित करते हुए देशराज कर्णवाल, उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री स्तर) समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त



नागरिकों तक पहुँचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

शिविर में 68 समस्याएं हुई दर्ज

उन्होंने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा कुल 68 समस्याएं दर्ज कराई गईं। पानी की टंकी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत विभाग के बिल,

जलभराव, चकरोड़, साफ-सफाई तथा राजस्व भूमि से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। इनमें से लगभग 29 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टालों का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया।

समय से निस्तारित करें शिकायतें

अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीआर चौहान

ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है, उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। शिविर में अध्यक्ष रूड़की डॉ. मधु सिंह, सचिव, सुनील, अंशुल, आशीष, आशुतोष, विवेक, खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गेय सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

विकास खण्ड नारसन में लगे शिविर में आयी 80 शिकायतें

अपर सचिव उत्तराखंड अनुराधा पॉल की अध्यक्षता में विकासखंड लक्सर की न्याय पंचायत हबीबपुर कुंडी में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 652 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 785 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 2030 लोगों ने प्रतिभाग किया। बहुउद्देशीय शिविर में कुल 80 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 75 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित

विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए।

सरकार जनता की समस्याओं पर गंभीर

शिविर में संबोधित करते हुए अपर सचिव उत्तराखंड अनुराधा पॉल ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है। उनकी परेशानियों को देखते हुए हर ग्राम पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग और गांव के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामचंद्र दीपक सेठ ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

ये रहे मौजूद: इस दौरान ग्राम प्रधान सुधा देवी, रखी चौहान, निकी, वंदना, वंदना, अनीता देवी सहदेव कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य बबलेश देवी, सुरैया, बबली तनुजा सहित जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी एवं भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

कोटद्वार में वीरबाला तीलू रौतेली को मिला सम्मान, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूजी का जताया आभार



पथ प्रवाह, कोटद्वार।

वीरबाला तीलू रौतेली विचार मंच के सदस्यों ने कोटद्वार के निम्बूचौड़ स्थित उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूजी भूषण के निजी आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की और कोटद्वार लालबती चौक पर वीरबाला तीलू रौतेली की मूर्ति को साइड से हटाकर मुख्य चौराहे पर स्थापित कराए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूजी भूषण ने कहा कि कोटद्वार विधायक बनने से पूर्व से ही वीरबाला तीलू रौतेली विचार मंच द्वारा लालबती चौक पर मूर्ति को प्रमुख स्थान पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों के कारण यह कार्य कठिन प्रतीत हो रहा था। एक कार्यक्रम के दौरान मंच के पदाधिकारियों ने उन्हें इस विषय से अवगत

कराया, जिसके बाद संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला गया। उन्होंने कहा कि मूर्ति के मुख्य चौराहे पर स्थापित होने से जहां वीरबाला तीलू रौतेली को उचित सम्मान मिलेगा, वहीं यह स्थान शहर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र भी बनेगा।

विचार मंच की अध्यक्ष बीना रावत ने बताया कि विधायक ऋतु खण्डूजी भूषण से इस विषय पर चर्चा होते ही उन्होंने शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

ऋतु खण्डूजी भूषण ने मूर्ति स्थापना में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोटद्वार मेयर शैलेन्द्र सिंह रावत, पुलिस प्रशासन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंच के सचिव महेंद्र सिंह रावत, उपाध्यक्ष जयवीर रावत, कोषाध्यक्ष अर्जुन रावत सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

भराड़ीसैण विधानसभा परिसर में 54.10 लाख की लागत से 100 केवीए सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ

पथ प्रवाह, कोटद्वार

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूजी भूषण ने जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) स्थित उत्तराखंड विधानसभा परिसर में 54.10 लाख रुपये की लागत से स्थापित 100 केवीए क्षमता के सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन पर समस्त उत्तराखंडवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इसे भराड़ीसैण को पर्यावरण-अनुकूल, ऊर्जा-आत्मनिर्भर एवं आधुनिक विधानसंगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूजी ने बताया कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), चमोली द्वारा विधानसभा परिसर में नेट मीटरिंग आधारित सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया गया है। इस संयंत्र से प्रतिमाह लगभग 12,000 यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ विद्युत ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। औसतन 6 प्रति यूनिट की दर से इस सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विधानसभा को प्रतिमाह लगभग 72,000 की बचत होगी, जो वार्षिक रूप से लगभग 8.64 लाख के बराबर है। इस सोलर पावर प्लांट का परिचालन जीवन 25 वर्षों से अधिक का है, जिससे दीर्घकाल तक उत्तराखंड विधानसभा



को आर्थिक, पर्यावरणीय एवं संरचनात्मक लाभ प्राप्त होंगे।

श्रीमती ऋतु खण्डूजी भूषण ने कहा कि भराड़ीसैण (गैरसैण) केवल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक चेतना और पहाड़ की आत्मा का प्रतीक है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से ही वे भराड़ीसैण विधानसभा परिसर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रही हैं। उनके कार्यकाल में इस परिसर में उत्तराखंड विधानसभा का डिजिटाइजेशन, महिला सुरक्षा कर्मियों के लिए आधुनिक हॉस्टल की व्यवस्था, मीडिया कर्मियों हेतु मीडिया हॉस्टल का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का संचालन तथा विधानसभा परिसर को आम जनमानस के

लिए खोलने जैसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों का उद्देश्य भराड़ीसैण को एक आदर्श, पारदर्शी, तकनीक-समर्थ और जन-सुलभ लोकतांत्रिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि आम नागरिक भी विधानसभा से सीधे जुड़ाव महसूस कर सकें।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूजी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से भराड़ीसैण को हरित ऊर्जा, सतत विकास और आधुनिक अवसंरचना का मॉडल बनाया जा रहा है।



मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का माता रणकोची धाम से जनसंवाद, 170.15 करोड़ की सौगात

पथ प्रवाह, चम्पावत।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जनपद चम्पावत स्थित पावन माता रणकोची धाम में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात मंदिर परिसर में आयोजित भव्य जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधे संवाद किया और विकास व जनकल्याण के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल' के अंतर्गत जनपद के ऐतिहासिक मंदिरों के पुजारियों को 'कला, परंपरा और पहचान' किट वितरित की। इन किटों में वाद्य यंत्र, धार्मिक पुस्तकें, पूजा सामग्री सहित अन्य सांस्कृतिक सामग्री शामिल रही। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ-साथ नशा मुक्त भारत एवं नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को सशक्त करना है। माता रणकोची मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनपद चम्पावत के लिए कुल 170.15 करोड़ की लागत से 20



विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इनमें 33.95 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण तथा 136.20 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं सहायता सामग्री भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चम्पावत के समग्र विकास हेतु 7

महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। इनमें सीम, खेत, चूका एवं सौराई क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य, तल्लादेश क्षेत्र के मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पूर्णागिरि मेला-2026 के सुचारु संचालन हेतु 2.5 करोड़ की धनराशि, विधानसभा चम्पावत के मंचकारी मोटर मार्ग तथा रमैला-गागरी-दमतोला मोटर मार्ग का डामरीकरण, जिला चिकित्सालय चम्पावत की निर्माणाधीन क्रिटिकल यूनिट में



लिफ्ट सहित मरीज सुविधाओं का विस्तार, ग्राम सभा नीड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एनएम उपकेंद्र) की स्थापना तथा चम्पावत में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 15 नाली भूमि उपलब्ध कराए जाने की घोषणाएँ शामिल रहीं।

जनसंवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चम्पावत आस्था,

संस्कृति और इतिहास से समृद्ध भूमि है, जहाँ आस्था जीवन को दिशा देने वाली चेतना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी संस्कृति में निहित होती है और माता रणकोची मंदिर का विकास सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सशक्त प्रयास है। सरकार का मूल मंत्र 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' बताते हुए उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में जनसमस्याओं का समाधान हुआ है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोविन्द सामन्त, नगर पालिका अध्यक्ष टनकपुर विपिन वर्मा, नगर पंचायत बनबसा अध्यक्ष रेखा देवी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख चम्पावत अंचला बोहरा, नगर पालिका अध्यक्ष चम्पावत प्रेमा पाण्डेय, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल माहरा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, जिला महामंत्री मुकेश कलखुडिया, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव, सूरज प्रहरी, शंकर पांडे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

शिक्षा ही विकसित उत्तराखंड की सबसे मजबूत नींव : त्रिवेन्द्र सिंह रावत

उत्तराखंड एजुकेशन समिट में शिक्षा के भविष्य पर हुआ गहन मंथन

पथ प्रवाह, देहरादून

शिक्षा के बिना किसी भी राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। विकसित उत्तराखंड की सबसे मजबूत नींव गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित शिक्षा प्रणाली पर ही टिकी है,' यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मायादेवी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'उत्तराखंड एजुकेशन समिट' के प्रथम संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। इस महत्वपूर्ण मंच पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे वैश्विक परिवर्तनों, नई तकनीकों और चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश



डाला। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी, कौशल आधारित और शोध केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है, ताकि युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सके और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। समिट के दौरान शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और अकादमिक उत्कृष्टता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षाविदों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन शिक्षा के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ।

एक नजर

प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की हरकी पैड़ी इकाई ने मनायी लोहड़ी

खुशीयों का पर्व है लोहड़ी-डॉ.विशाल गर्ग



पथ प्रवाह, हरिद्वार। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की हरकी पैड़ी इकाई द्वारा हरकी पैड़ी पर धूमधाम से लोहड़ी पर्व मनाया गया। हरकी पैड़ी इकाई के अध्यक्ष सर्वेश्वर मूर्ति भट्ट के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉ.विशाल गर्ग ने सभी व्यापारियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। डॉ.विशाल गर्ग ने कहा कि भारत पर्वों और संस्कृतियों का गुलदस्ता है। मिलजुल कर पर्व मनाने से सामाजिक समरसता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि लोहड़ी खुशीयों का पर्व है। पर्व में समाज के वंचित वर्ग को भी शामिल करें। इससे पर्व की खुशीयां दोगुनी हो जाती हैं। हरकी पैड़ी इकाई के अध्यक्ष सर्वेश्वर मूर्ति भट्ट ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि व्यापारी सामाजिक सरोकारों में मुख्य निभाते हैं। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार कश्यप, प्रदेश सचिव मयंक मूर्ति भट्ट, जिला अध्यक्ष डॉ.विशाल गर्ग, तहसील अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, शहर अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शहर महामंत्री विमल सक्सेना, जिला महामंत्री अश्वनी शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विशाल मूर्ति भट्ट सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल रहे।

हरकी पैड़ी पर अरबी शेख की वेशभूषा में घूमकर सनसनी फैलाने वाले युवकों का पुलिस एक्ट में चालान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

मंगलवार को हरकी पैड़ी क्षेत्र में अरबी शेख की वेशभूषा में घूमकर सनसनी फैलाने वाले दोनों युवकों को कोतवाली नगर पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है। पूछताछ में पता चला कि रील बनाकर लाइक और कमेंट बटारेने के लिए उन्होंने यह हरकत की।

दिन में यह यह मामला तूल पकड़ गया था, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों लड़कों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले। दोनों के बारे में सुरंग लगने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के वर्तमान में रावली महदूद सिडकुल में रह रहे हैं। इनमें एक का नाम प्रिंस पुत्र सोमपाल मूल निवासी जनपद बिजनौर और दूसरे का नवीन कुमार पुत्र मुन्ना निवासी रावली महदूद, सिडकुल हरिद्वार है। पूछताछ में बताया कि इससे पहले पेंटागन मॉल, शिवालिक नगर में भी इसी तरह की रील बनायी थी, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया था। पुलिस को बताया कि उनका मकसद किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दोनों ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की वीडियो न बनाने की बात कही। हरिद्वार पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी घटना की सत्यता जाने बिना उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार न करें।

हरकी पैड़ी पर शेख के लिबास में घूमते दिखे थे दो संदिग्ध युवक

बता दें हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र में मंगलवार को शेख के लिबास में दो युवक



घूमते नजर आए थे। इन पर जब स्थानीय पुरोहितों की नजर गई तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुट गई थी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। लोग इसे माहौल खराब करने की साजिश बता रहे थे। इन दो युवकों के संदिग्ध अवस्था में घूमते पाए जाने पर तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, बाद में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने भी पुलिस प्रशासन को उक्त वीडियो देकर कार्रवाई की मांग की

थी। उज्ज्वल पंडित ने बताया था कि बिना किसी पूर्व अनुमति के दोनों युवक हरकी पैड़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच घूम रहे हैं। जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। सूचना के आधार पर हरकी पैड़ी चौकी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों युवकों की तलाश एवं पहचान संबंधी जांच शुरू कर दी थी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि दोनों युवक किस उद्देश्य से धार्मिक नगरी हरिद्वार और विशेष रूप से हरकी पैड़ी क्षेत्र में मौजूद थे।